

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 21 मार्च, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से अतिरिक्त धनराशि के व्यावर्तन की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 215/2005-06, दिनांक 11.12.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 3-दो(6)/XXXVI(1)/2006-1-दो(6)/06, दिनांक 11.5.2006 एवं शासनादेश संख्या: 6-दो(6)/XXXVI(1)/2006-1-दो(6)/06, दिनांक 12.10.2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाधिवक्ता कार्यालय के उपयोगार्थ संलग्न बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में अंकित मद में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित मद में कुल रु० 40,00,000/- (चालीस लाख रुपये मात्र) की धनराशि के व्यावर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) उपर्युक्त धनराशि बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों तथा शासन के अन्य आदेशों का पालन किया जाय ।
- (2) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।
- (3) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेतर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता(काउन्सिल)-03-महाधिवक्ता-00-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-122/XXVII(5)/2007, दिनांक 19.3.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संलग्नक- यथोक्त ।

संख्या : 9-दो(6)/XXXVI(1)/2006-1-दो(6)/06-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
- 4- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

प्रत्येक अधिकारी का नाम- महाविद्यता, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
प्रशासनिक विभाग का नाम- न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है ।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	धनराशि हजार रूपयों में अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता(काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता-00	31000	26000	4000-क	2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-03-महाधिवक्ता-00	19000	27000	क-मितव्ययता के कारण उपलब्ध वक्त ख-प्राविधान से अधिक आवश्यकता होने के कारण ।
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान	26000	1000	4000-क	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान	19000	27000	
कुल धनराशि	31000	1000	4000	4000	19000	27000	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट में अनुअल के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त विभाग

संख्या-122-क/ XXVII(5)/2007

देहरादून : दिनांक : 19 मार्च, 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहरनपुर रोड,
मानस, देहरादून ।

एन०एन०यमलियाल,
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या- 9-दो(6)XXXXVI(1)/2006-1-दो(6)06-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
5. वित्त अनुभाग-5/एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक ।

अम्बा से
(अलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

(अलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।